भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1539
मंगलवार, 28 जुलाई, 2026/6 श्रावण,1948(शक) को उत्तरार्थ

सहकारी चीनी मिल

1539. **श्री दर्शन सिंह चौधरीः**

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के तेन्दुखेड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में गन्ने की खेती की पर्याप्त संभावनाएं होने के बावजूद कोई सहकारी चीनी मिल नहीं है;

(ख) क्या सरकार को उक्त क्षेत्र में सहकारी चीनी मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है अथवा ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) क्या सरकार तेन्दुखेड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सहकारी चीनी मिल की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने अथवा वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता या कोई अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्य योजना, अनुमानित लागत, वित्तीय सहायता, समय-सीमा और इससे किसानों को क्या लाभ होने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) जी हां। मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कोई भी सहकारी चीनी मिल नहीं है। वर्तमान में नरसिंहपुर जिले में आठ निजी चीनी मिलें चल रही हैं, जिनमें से दो चीनी मिलें तेंदूखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कार्य कर रही हैं।

(ख) जी नहीं। केंद्र सरकार देश के किसी भी भाग में सहकारी चीनी मिल स्थापित नहीं करती है । इसके अलावा, चीनी उद्योग को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के दिनांक 31-08-1998 के प्रेस नोट द्वारा, जिनके लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग अपेक्षित होता है, उन उद्योगों की सूची से हटा दिया गया था।

(ग से ड.) देश में सहकारी चीनी मिलों के पुनरुद्धार हेतु सहकारिता मंत्रालय द्वारा विभिन्न पहलें की गई हैं। सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करने वाला सांविधिक संगठन, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), सहकारी चीनी मिलों के पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता एनसीडीसी द्वारा या तो सीधे सहकारी चीनी मिलों को अथवा संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से, एनसीडीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार समुचित परियोजना परीक्षण एवं परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर प्रदान की जाती है।

*****